

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1400  
उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

**केरल में पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन योजना**

†1400. श्री वी. के. श्रीकंदन:  
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पालक्काड़ जिले के अट्टापडी सहित केरल में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अंतर्गत शामिल लोगों की संख्या कितनी है;
- (ख) विगत दो वर्षों के दौरान केरल को पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;
- (ग) अट्टापडी, जहां अनेक जनजातीय बस्तियां विद्यमान हैं, सहित केरल में पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत आरंभ की गई प्रमुख परियोजनाओं और निर्मित अवसंरचनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने उक्त जिले सहित जनजातीय क्षेत्रों में उक्त योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री  
(श्री दुर्गादास उड्डे)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए बस्ती स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया है ताकि पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर किया जा सके। एकत्र किए गए आंकड़ों (31.01.2025 तक) के आधार पर, केरल राज्य में पीवीटीजी आबादी, जिले-वार, **अनुलग्नक- I** में सारणीबद्ध है। तथापि, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत कवर किए जाने वाले वास्तविक लाभार्थियों की संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है। अट्टापडी ब्लॉक सहित केरल राज्य को पीएम जनमन के तहत स्वीकृत निधियां और प्रगति का विवरण (14.01.2025 तक) **अनुलग्नक- II** में है। मिशन को 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गयी है।

“केरल में पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन योजना” के संबंध में श्री वी. के. श्रीकंदन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1400 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल में जिले-वार पीवीटीजी जनसंख्या (31.01.2025 तक)

| ज़िला    | पीवीटीजी जनसंख्या |
|----------|-------------------|
| कासरगोड  | 1668              |
| कोझिकोड  | 146               |
| मलप्पुरम | 3397              |
| पलक्कड़  | 4606*             |
| त्रिशूर  | 1232              |
| वायनाड   | 18462             |

\* पलक्कड़ के अट्टापडी ब्लॉक में पीवीटीजी की जनसंख्या 2674 है

अनुलग्नक-II

“केरल में पीवीटीजी के लिए पीएम-जनमन योजना” के संबंध में श्री वी. के. श्रीकंदन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1400 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अट्टापडी ब्लॉक सहित केरल में पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों/स्वीकृतियों का विवरण (14.01.2025 तक)

| मंत्रालय                             | उपाय                            | स्वीकृतियां         | प्रगति                     | स्वीकृत निधि<br>(केन्द्रीय अंश सहित<br>(जहां लागू हो))<br>करोड़ रुपये)** |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ग्रामीण विकास मंत्रालय               | पक्के मकान                      | 645 मकान            | 3 मकान पूरे हुए            | 15.41                                                                    |
| जल शक्ति मंत्रालय                    | पाइप से जलापूर्ति               | 95 गांव             | 1 गांव संतृप्त             | उपलब्ध नहीं है                                                           |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | सचल औषधि इकाइयां (एमएमयू)       | 22 एमएमयू स्वीकृत   | 22 एमएमयू कार्यात्मक       | 7.45                                                                     |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय         | आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसीएस) | 7 आंगनवाड़ी केन्द्र | 7 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित | 0.84                                                                     |
| शिक्षा मंत्रालय                      | छात्रावास                       | 4 छात्रावास         | -                          | 10.1                                                                     |
| विद्युत मंत्रालय                     | आवासों का ऊर्जाकरण              | 345 आवास            | 309 आवास विद्युतीकृत       | 0.86                                                                     |
| एमएनआरई                              | आवासों का ऊर्जाकरण (सौर ऊर्जा)  | 98                  | -                          | 0.49                                                                     |
| दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय       | मोबाइल टावर                     | 32 बस्तियाँ         | 13 बस्तियाँ कवर की गईं     | 6.3                                                                      |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय               | बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)     | 15 एमपीसी           | 4 एमपीसी का काम शुरू       | 9.00                                                                     |
|                                      | वीडीवीके की स्थापना             | 7 वीडिवीके          | 5 संचालित हैं              | 0.27                                                                     |

# संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

\*\* निर्मुक्तियां योजना के मानदंडों और व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं

\*\*\*\*\*